कार्यक्रम : राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन

स्थान : इंदिरा गाँधी स्टेडियम, नई दिल्ली

25 सितम्बर, 2021, प्रातः 10 बजे

मंच पर उपस्थित मंत्री परिषद में मेरे साथी भाई बी.एल वर्मा जी, इंटरनेशनल कॉपरेटिव अलायंस गलोबल के अध्यक्ष डॉ. Guarco जी, मंर पर उपस्थित सभी के नाम का उल्लेख करना चाहिए लेकिन समय अधिक हो जाने की वजह से महानुभावों का उल्लेख नहीं रहा हूँ मगर इन सब संस्थाओं के जो अध्यक्ष यहां पर बैठे हैं इन्होंने देश के सहकारिता आन्दोलन को यहां तक इस मुकाम तक पहुंचाने का काम किया है।

देश के कोने-कोने से आये इस सभागार में उपस्थित 21 सौ से ज्यादा सहकारिता आन्दोलनों के सभी नेता, सभी सहकारी बन्धुओं, बहनों और देश भर में कई जगह ऑनलाइन इस कार्यक्रम के साथ जुडे हुए सभी सहकारी क्षेत्र के कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों को मेरा प्रणाम !

आज शुरुआत मैं पंडित दीनदयाल जी की जन्म जयंती से करना चाहूंगा क्योंकि मेरे जैसे कई कार्यकर्ताओं का सहकार में आने की प्रेरणा का स्त्रोत दीनदयाल जी की अंत्योदय की नीति है। गरीब कल्याण और अंत्योदय की कल्पना सहकारिता के अलावा हो ही नहीं सकती और देश में सबसे पहले विकास की जब बात हुई तब सबसे पहले अंत्योदय की बात जिन्होंने की, वो पंडित दीनदयाल जी थे आज उनका जन्म दिन है। मेरे जैसे लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए यह दिन प्रेरणा प्राप्त करने का ये दिन है इसी दिन ये सहकारी सम्मेलन हो रहा है इसकी मुझे बहुत खुशी है।

मित्रों, आजादी के 75 साल के बाद और ऐसे समय पर जब सहकारिता आन्दोलन को सबसे ज्यादा जरूरत है तब देश के प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय बनाया इसलिए एक सहकारिता कार्यकर्ता के रूप में और आप सब की ओर से मैं

उनको बहुत-बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि सहकारिता आन्दोलन का अनुमोलन जो प्रधानमंत्री जी ने किया है अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर हम सब इसकी ताली बजाकर स्वागत करें और उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापन करें। मैं एक बार फिर से देशभर के करोड़ों सहकारिता के कार्यकर्ताओं की ओर से, सहकारिता के नेताओं की ओर से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ यह मेरी ओर से एक विशेष धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि यह मेरी रुचि का विषय है और देश में सबसे पहला सहकारिता मंत्री बनने का मौका उन्होंने मुझे दिया है यह मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। आज जब हम यहां खड़े हैं और सहकारिता आन्दोलन को बल देने की, गति देने की, दिशा देने की एक नई शुरुआत होने जा रही है, मैं इतना कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने इस मंत्रालय की स्थापना की है और मैं सहकारिता मंत्री होने के नाते देशभर के सहकारिता के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बताना चाहता हूँ कि निक्लिक्शन का टाइम समाप्त हुआ है, प्रायोरिटी का टाइम शुरू हुआ है, आइए सब साथ में मिलकर सहकारिता को आगे बढाते हैं। देश के विकास में सहकारिता बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। देश के विकास में सहकारिता का योगदान आज भी है, मगर बहुत सारे आयामों में, आयामों तक हमें पहुंचना बाकी है। हमें इसे नए सिरे से सोचना पड़ेगा, नए सिरे से रेखांकित करना पडेगा। हमारे काम का दायरा बढ़ाना पडेगा, काम में स्थिरता लानी पड़ेगी, काम में पारदर्शिता भी लानी पड़ेगी और काम में सहकारिता की भावना को स्वभाव की तरह, संस्कार की तरह घुल मिलकर सहकारिता के आन्दोलन को आगे बढ़ाना पडेगा। देश के करोड़ों किसान, वंचितों, पिछड़े, दलित, गरीब और उपेक्षित महिलाओं विकास का मार्ग केवल और केवल सहकारिता के माध्यम से ही हो सकता है और कोई मार्ग नहीं है। कई लोग सहकारिता को प्रासंगिकता पर सवाल उठाते हैं उनको लगता है कि सहकारिता आन्दोलन इरेलवेन्ट हो गया है। मैं मन से और नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि सहकारिता आन्दोलन सबसे ज्यादा प्रासंगिक कभी था तो अभी है और मंजिल पाना अभी बाकी है। हर गाँव को कॉपरेटिव के साथ जोड़कर सहकार से समृद्धि के मंत्र से समृद्ध बनाना और समृद्ध गांव से देश को

समृद्ध बनाना, यही सहकारी आन्दोलन की भूमिका होगी। सहकारिता शब्द सह और कार्य इन दो शब्दों से मिलकर बना है। मिलजुलकर एक लक्ष्य के साथ भातृ भाव से एक दिशा में काम करना ही सहकारिता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि देश के करोड़ों लोगों की, कॉपरेटिव क्षेत्र में काम करने वालों की ताकत शायद कम होगी, हमारी आर्थिक ताकत भी शायद कम होगी मगर हमारी संख्या इतनी अधिक है अगर इसको एक बार हम कॉपरेटिव के माध्यम से एकजुट करते हैं तो एक प्रचंड ताकत की निर्मिती होती है जिसको कोई हरा नहीं सकता, आत्मविश्वास के साथ सहकारिता आन्दोलन से एक नई शुरुआत करने का समय आ गया है। मोदी जी ने एक मंत्र दिया है सहकार से समृद्धि का और उन्होंने जो 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनोमी का लक्ष्य रखा है मैं आज मोदी जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सहकरिता क्षेत्र भी आपके 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनोमी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ऐड़ी चोटी का जोर लगा देगा।

मित्रों, सहकारिता से जो हमारी ताकत बनती है वो ताकत देश को समृद्ध करने की दिशा में लगेगी इसका मुझे विश्वास है। सहकारिता आन्दोलन भारत के ग्रामीण समाज की प्रगति भी करेगा और एक नई सामाजिक पूंजी का कॉन्सेप्ट भी तैयार करेगा। पूंजी की दुनिया भर में कई व्याख्याएं हैं हम 10000 साल से संस्कृति का वहन करने वाले लोग हैं । सामाजिक पूंजी का कॉन्सेप्ट सामाजिक पूंजी का वह विचार और संस्कार है जो हमारे सहकारिता आन्दोलन को बहुत आगे ले जाएगा । कई देशों में सहकारिता कानून से अस्तित्व में आई है। कई देशों में सहकारिता छोटे-छोटे पैक्स और बाकी सहकारिता समितियों के गठन से अस्तित्व में आई है। भारत में यह व्यवस्था के लिए इसका होना जरूरी है। भारत की जनता के स्वभाव में सहकारिता घुल मिल गयी है। लोगों के संस्कार के अन्दर सहकारिता है ये कोई उधार लिया हुआ कॉन्सेप्ट नहीं है, यह हमारे काम को स्वत: प्रकट हुआ कॉन्सेप्ट है इसलिए भारत में कभी सहकारिता आन्दोलन इरेलेवेन्ट नहीं हो सकता।

मित्रों, मैं बहुत समय से, लगभग 25 साल से सहकारिता आन्दोलन से जुडा हुआ हूँ। छोटी से छोटी इकाई से लेकर राज्य स्तर की इकाई तक मैंने काम किया है। मैंने देखा बहुत सारे संकट आते हैं, सरकारें परिपत्र निकालती हैं। परिपत्र की मॉनिटरिंग करनी पड़ती है मगर हमारे आन्दोलन सहकारिता के कोई परिपत्र की राह नहीं देखते, बाढ़ आती है तो गांव की पैक्स खडी हो जाती हैं और सब को खाना खिलाने का काम करती है, उनको आसरा देने का काम करती है, डिस्ट्रिक में कॉपरेटिव बैंक कितना खर्च हो जाएगा इसकी चिन्ता नहीं करता, कितना डिविडेन्ट कम हो जाएगा, इसकी चिन्ता नहीं करता अपने कार्य क्षेत्र के अन्दर चाहे अकाल हो, चाहे साइक्लोन आया हो, चाहे बाढ या बारिश ज्यादा आयी हो काम के लिए एकजुट होकर सभी खडे हो जाते हैं। सहकारिता आन्दोलनों ने इस समय् देश ढेर सारे संकटों में बाहर निकालने के लिए अपना योगदान दिया है। सहकारिता भारत के लिए नई नहीं है। 1904 से लेकर अभी तक भारत की सहकारिता आन्दोलन ने ढेर सारे मुकाम देखे हैं, बहुत सारे चढाई-ऊँचाई को भी हमने देखा है, कभी हम गिरे, कभी हम संभले, कभी हम आगे बढे, तेजी से आगे बढे परन्तु ये गति नहीं हुई और मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि ये गति नहीं होनी चाहिए। आज इस अवसर पर सहकारिता आन्दोलन को बल देने वाले माधवराव गोडबोले, वैकुन्टभाई मेहता, त्रिभुवन दास पटेल, विठ्ठलराव विखे पाटिल, यशवंत राव च्वहाण, धनंजय राव गाडगिल और लक्ष्मण राव नामदार जैसे कई लोगों को मैं आज यहां याद करता हूँ और उनको प्रणाम करके उनके आशीर्वाद से इस आन्दोलन को आगे बढाने के लिए हमें एक नई गति दें ऐसी प्रार्थना करता हूँ।

मित्रों, मुझे कई लोग मिलते हैं, कॉरपोरेट क्षेत्र के लोग भी मिलते हैं, पत्रकार भी मिलते हैं और अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी मुझे मिलते हैं, साफ अर्थ में मुझसे पूछते हैं कि सहकारिता आन्दोलन रेलेवेन्ट है क्या? उसकी प्रासंगिता आज भी बनी हुई है उससे क्या सिद्ध होगा? मैं आज कुछ सहकारी आन्दोलन की गुड प्रैक्टिस आपके सामने बताना चाहता हूँ। मैं गुजरात से आता हूँ। मैं अमूल की बात करना चाहता

हूँ। अमूल का जन्म सरदार पटेल की दूरदर्शिता से हुआ। 1946 में अंग्रेजों ने एक फैसला लिया कि किसानों को कम्पलसरी फर्जियात के रूप में अपना दूध एक प्राइवेट कंपनी को देना पडेगा, इसके खिलाफ एक आन्दोलन हुआ। खेडा जिले के अन्दर सरदार पटेल ने त्रिभुवनभाई को कहा कि जब तक दूध बेचने की व्यवस्था नहीं करते तब तक इसके खिलाफ आन्दोलन कभी सफल नहीं होगा और वहां से अमूल की एक शुरुआतत हुई। सरदार पटेल के मार्गदर्शन में त्रिभुवनभाई पटेल ने दो प्राथमिक ग्राम दूध उत्पादक समितियों का पंजीकरण किया और इसमें 80 किसान जुड़े सिर्फ 80 किसान और वो अमूल आज कहां है। 2020-21 में उसका ग्रुप टर्नओवर 53 हजार करोड रुपये को पार कर चुका है। एक दिन में लगभग 30 मिलियन दूध का प्रबन्धन हमारा कॉपरेटिव संस्थान करता है। इसके 36 लाख किसान परिवार जुड़े हुए हैं और इसने विशेषकर महिलाओं को एम्पॉवर करने का काम किया है। मैंने तो गांव में देखा है। गुजरात में शनिवार को जब महिला के हाथ में चैक आता है या कैश आता है तो उसके चेहरे पर हंसी देखकर मन में बहुत अन्दर तक शान्ति मिलती है। 36 लाख किसान परिवारों को अमूल ने आज अपने साथ जोडा हुआ है। 18 जिलों का ये फैडरेशन है। 87 से ज्यादा डेयरी के मैनुफैक्चिरंग प्लांट बनाए हैं और उसकी प्रबंधन क्षमता 39 मिलियन टन की है। इंस्टॉल कैपेसिटी 39 मिलियन टन दूध को प्रोसेस करने की है। आप कल्पना कर सकते हैं बडी से बडी कॉरपोरेट डेयरी जो नहीं कर सकती वो हमारे अमूल ने करके दिखाया है और मेरा मानना है कि यही उदहारण लेकर हमको आगे बढना चाहिए। लिज्जत पापड़ बहुत कम लोगों को यहां पर मालूम होगा। लिज्जत पापड कॉपरेटिव 1959 में एक गुजराती महिला जस्वंतीबेन पोपट ने 80 बहनों को साथ में लेकर पापड़ बनाने की शुरुआत की थी । 2019 में उनका कारोबार 1600 करोड़ से ज्यादा का है और 80 करोड़ निर्यात करती हैं। 45 हजार महिलाएं लिज्जत के कॉपरेटिव आन्दोलन से जुडी हैं और ये सक्सेस स्टोरी देशभर की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। अमूल और लिज्जत दोनों आज सफल है तो देश की महिलाओं का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। दूध भरने में भी और पापड़ बनाने में भी। इफ्को जो आज हमारे यजमान हैं, चेयरमैन साहब भी यहां बैठें

हैं, एम.डी. अवस्थी जी भी बैठे हैं। इफ्को ने देश की हरित क्रांति को एक नई दिशा देने का काम किया है। 1967 में 57 कॉपरेटिव के साथ एक स्पेसीफाइड सोसायटी बनी और वो बढ़ते-बढ़ते आज 36 हजार से ज्यादा कॉपरेटिव को मेम्बर बनाकर लगभग 5.5 करोड़ किसानों को उसका लाभांश पहुंचाती है । आप कल्पना कर सकते हैं एक बहुत बडी कंपनी अगर कुछ कमायेगी तो उसका सबसे बडा हिस्सा उसके मालिक के पास जाएगा और इफ्को जो कुछ भी कमाएगी इसका पाई-पाई इन किसानों के घर में जाएगा इसी को कॉपरेटिव कहते हैं। आज इफ्को ने 2-3 और कॉपरेटिव को साथ में रखकर देश की उवर्रक की जिम्मेदारी उठाई है और मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ चेयरमैन साहब का और अवस्थी जी का कि इन्होंने नैनो टैक्नोलॉजी को जमीन पर उतारकर बहुत बडा काम किया और मुझे पूरा विश्वास है कि कॉपरेटिव संस्थाओं के माध्यम से आने वाले दिनों में वो दिन दूर नहीं कि उवर्रक खाद इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आत्मनिर्भर बनेंगे और हमारा उवर्रक हमारे देश में मिलेगा। इसी तरह से Kribhco भी लगभग 9500 समितियों का बना हुआ एक संघ है उसकी मूडी शेयर पद्दति मूडी लगभग 388 करोड है, शेयर धारकों को एक साल में 2118 करोड रुपये का लाभांश Kribhco ने दिया है। ये सब सक्सेस स्टोरी है और इतना ही नहीं है, बहुत लम्बी सूची है। नेफेड है, मैं मणिपुर गया था रेणु हथकरघा हस्तशिल्प 75 साल से एक गति के साथ कॉपरेटिव में अपना योगदान करता रहा है। 1925 से चल रही उरानुंगल श्रम अनुबंध सहकारी समिति केरल, टोटा मारदा सहकारी संघ द्रावणगिरी कर्नाटक, कोझीकोट जिला सहकारी हॉस्पिटल ऐसे बहुत से संस्थान हैं जिन्होंने सहकारी आन्दोलनों के माध्यम से इसका उदाहरण प्रस्तुत किया है। छोटे-छोटे लोगों से पूंजी इक्कठाकर देश के अर्थ तंत्र और देश के विकास में योगदान दे सकते हैं और मुनाफा छोटे-छोटे निवेशकों के घर में कैसे जा सकता है आज लगभग सारे संस्थानों के कर्ताधर्ता यहीं पर हैं, प्रबंध निदेशक हैं, चेयरमैंन हैं, डायरेक्टर हैं, मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ हमें काफी कुछ करना बाकी है। क्या इस श्रृंखला में हमारी ये सफल कॉपरेटिव अपना योगदान नहीं दे सकती है, क्या अच्छे बीज क्यों विदेश से लाने पडेंगे, बीज के क्षेत्र में हम

आत्मनिर्भर नहीं हो सकते, क्या कोई कॉपरेटिव चैलेंज एक्सेप्ट करकर किसानों की उपज का ट्रेडिंग हाउस नहीं बन सकते हैं जिसके माध्यम से छोटी-छोटी मंडियां अपनी उपजों को विदेश में एक्सपोर्ट कर सकें। निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग का दुनियाभर में बाजार फैला हुआ है, छोटा किसान नहीं कर पायेगा और किसी को रुचि भी नहीं है और करेगा तो भी किसान वहीं का वहीं रह जाएगा। अगर ये हमारे कॉपरेटिव एक-एक क्षेत्र को पकड़कर एक्सपेंशन का काम करे तो मुझे विश्वास है कि 5 साल के अन्दर कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहां कॉपरेटिव की पैठ नहीं होगी। सहकारिता मंत्रालय इसलिए ही बनाया गया है। कॉपरेटिव को मजबूत करना है, कॉपरेटिव का ग्राफ बढाना है, कॉपरेटिव के अन्दर पारदर्शिता लानी है, कॉपरेटिव संस्थाओं को मोर्डनाइज करना है, कम्प्यूटराइज करना है और इसे स्पर्धा में टिकने वाली कॉपरेटिव बनाना है। इन सारी चीजों को करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने यह मंत्रालय बनाया है।

मित्रों, आप सब लोग कॉपरेटिव संस्थाओं से जुडे हुए लोग हैं। मैं आज आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि जब तक जामवंत जी ने हनुमान जी को नहीं कहा कि हनुमान जी रामेश्वरम से लंका तक समुद्र लांध सकते हो उनको विश्वास नहीं था। जब जामवंत जी ने कहा कि हनुमान तुम हिम्मत करो, समुद्र तुम लांघ सकते हो, हनुमान जी ने छलांग लगाई और समुद्र लांघ गए। मैं आपको क्या बताऊंगा कॉपरेटिव क्या है आप सब मुझसे ज्यादा अनुभवी कॉपरेटर हैं परन्तु मैं आज कुछ चीजें बताना चाहता हूँ जिससे हमें हमारी स्ट्रेन्थ का परिचय हो।

मित्रों, लगभग 91% गांव ऐसे हैं जहां छोटी बड़ी कॉपरेटिव संस्था काम करती है। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं होगा जिसके 91% गांव में कॉपरेटिव की उपस्थित हो। 8 लाख 55 हजार से ज्यादा रजिस्टर सहकारी समितियां हैं। लगभग 8.5 लाख क्रेडिट सहकारी समितियां हैं, लोन न देने वाली सहकारी समितियां 60 लाख से ज्यादा हैं, राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संघ 17 से ज्यादा हैं, राज्य स्तरीय सहकारी बैंक 33 हैं, जिला

स्तरीय सहकारी बैंक 363 हैं और लगभग-लगभग 95 हजार में से 63 हजार बैंक्स काम कर रहे हैं। एक दृष्टि से देखें तो हर 10वें गांव पर एक पैक्स है। मैं आगे बताऊंगा कि ये संतोषजनक स्थिति नहीं है मगर हर 10वें गांव में एक पैक्स होना दुनिया के सहकारिता के आंकडों का जब अध्ययन करते हैं तो अपने आप में एक बहुत बडी उपलब्धि है। ये पैक्स ही माध्यम है किसान का कल्याण करने का, ये पैक्स ही माध्यम है जो सरकार कम ब्याज पर लोन देती है। किसान के लिए उसको पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के लिए ये पैक्स ही माध्यम है, उस तक खेती के लिए उपयोगी चीजों को पहुंचाने के लिए इन पैक्स को मजबूत करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। मैं अंत में पैक्स पर बात करुंगा और मैं बताना चाहता हूँ कि कृषि ऋण वितरण का 29% कॉपरेटिव व्यवस्था से जाता है। उवर्रक वितरण 35% कॉपरेटिव से जाता है। उवर्रक का उत्पादन, खाद का उत्पादन वो भी लगभग 30% करता है। चीनी का उत्पादन, देश की कुल चीनी का उत्पादन 31% कॉपरेटिव चीनी मिलें करती हैं। तकलीस पिंडल 29%, दूध की खरीदी और उत्पादन 20%, गेहूं की खरीदी 13% कॉपरेटिव करती है। धान की खरीदी 20% करती है और मत्स्य क्षेत्र में भी कॉपरेटिव का योगदान 21% है।

मित्रों, बहुत मजबूत प्लेटफार्म पर आज हम खडे हैं। अब समय आ गया है कि नए लक्ष्य तय करना और नए लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए आगे बढना है। ये प्लेटफार्म भारत के कॉपरेटिव आन्दोलन के पुरखों ने हमें दिया है उस प्लेटफार्म पर एक मजबूत बहुमंजिला इमारत बनाने का काम यहां हॉल में बैठे हुए और ऑनलाइन जुडे हुए सभी कार्यकर्ताओं का हैं और इसीलिए मोदी जी ने इस सहकारिता आन्दोलन को गति देने के लिए सहकारिता मंत्रालय की रचना की है। हमारी सफलता चार ही चीजों से हो सकती है संकल्प शक्ति, साफ नियत, परिश्रम और संघ भाव से काम करना। ये चार मूल सिद्धांत है अगर हम सब कॉपरेटिव के अन्दर इसको लेटर एण्ड स्प्रीट में पहुंचाते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे आन्दोलन को गति मिलेगी। नरेन्द्र मोदी जी ने जो सहकारिता मंत्रालय बनाया है उसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में विकास को पहुंचाना और ग्रामीण क्षेत्र

में हर वंचित तक पहुंचाने की चुनौती की जिम्मेदारी सहकारिता मंत्रालय की है और इसको एक स्वदेशी यंत्रणा बनाने की जिम्मेदारी भी सहकारिता मंत्रालय की है।

मित्रों, सात साल में कृषि क्षेत्र में मोदी जी ने अमूलचूक परिर्वतन किया है मैं सिर्फ बजटीय आवंटन की बात करना चाहता हूँ। 2009-10 में कृषि का बजट 12 हजार करोड था मैं फिर से रिपीट करता हूँ 12 हजार करोड, बहुत बड़ा लागत है मगर 2020-21 में इस बजट को बढ़ाकर 1,34,499 करोड रुपये किया है। मैं यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कृषि क्षेत्र नरेन्द्र मोदी सरकार की प्राथमिकता है और कृषि क्षेत्र की ये जो प्राथमिकता है उसको उसके लक्ष्यों तक पहुंचाना सहकारिता के बगैर संभव नहीं है। हमने ढ़ेर सारे किसानों को सपोर्ट देने की बात की है। स्वामीनाथन आयोग आया तब से बात करते थे कि किसानों की आय बढ़नी चाहिए, लागत से 50% ज्यादा होना चाहिए, कोई नहीं देता था, पहली बार नरेन्द्र मोदी सरकार ने लागत से ज्यादा एमएसपी तय कर कर किसानों को फायदा पहुंचाने का काम किया है।

मित्रों, मैं बहुत सारी रिपोर्ट कोट कर सकता हूं जिसमें स्पिरिट थी मगर ये वास्तव में होती नहीं थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से देश के 11 करोड़ किसानों को लगभग 1 लाख 58 हजार करोड रुपये डाइरेक्ट डीबीटी से पहुंचाया गया है।

मित्रों, स्टार्ट अप शुरु करने का एक अभियान चला है। दस हजार नए एफपीओ बनाए जाने है। लगभग-लगभग 6865 करोड़ रुपये वित्त पोषण के लिए अलग से खर्च किया जाना है। ई-नाम मंडी की योजना लाए हैं, स्वाइल हेल्थ कार्ड दिया है और इन सारी चीजों में सहकारिता क्षेत्र का और पैक्स का एक रोल है। हमें सारी चीजों को अपनी पैक्स के अन्दर मजबूती से इसका अध्यन करके इसकी इम्पलिमेंटिंग ऐजेंसी गांव स्तर पर बनाने की शुरुआत करनी पड़ेगी तभी ये सारी चीजें नीचे तक पहुंचा पाएंगे।

मित्रों, सहकारिता मंत्रालय का जो गठन किया है इस बारे में कई सारे लोग कहते हैं कि यह स्टेट सबजेक्ट है। मैं स्टेट और सेंटर के झगडे में पडना नहीं चाहता। इसका

कानूनी जवाब आराम से दिया जा सकता है मगर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में बना सहकारिता मंत्रालय सभी राज्यों के साथ सहकार करके चलेगा, यह किसी से संघर्ष करने के लिए नहीं बना है इसलिए किसी को यह सोचने की जरूरत नहीं है कि यह स्टेट सबजेक्ट है या सेंटर सबजेक्ट है, हम सबकी मदद कर सकते हैं। राज्यों की भी करेंगे और आन्दोलन को आगे बढाएंगे। सहकारी समितियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का काम सहकारिता मंत्रालय के तात्वाधान में होगा। मल्टी स्टेट कॉपरेटिव को उसको सुगम बनाने के लिए हम बहुत कम समय के अन्दर एक्ट में बहुत सारे बदलाव लेकर आ रहे हैं। विकास पथ पर आगे बढ़ने के लिए यह एक बहुत बडी बात है। नई सहकार नीति पहले अटल जी लेकर आए थे 2002 में हमने तय किया है कि कुछ समय के अन्दर ही अब 20220-21 में मोदी जी लेकर आएं हैं। ये आजादी का 75वां साल है। अमृत महोत्सव में नई सहकार नीति को बनाने की हम शुरुआत भी करेंगे, पैक्स को मजबूत भी करेंगे। 63 हजार पैक्स 6 लाख गांवों के बीच में कम है। हम एक लक्ष्य रखेंगे आने वाले पांच साल के अन्दर हर दूसरे गांव में पैक्स हो जाए। पैक्स की संख्या को 65 हजार से बढ़ाकर 3 लाख तक पहुंचाने का उचित कानूनी खाका तैयार करने का काम ये सहकार मंत्रालय करेगा और वो एडवाइजरी होगा स्टेट के पास भेजेंगे। स्टेट अपने कानूनों में परिर्वतन करेगा सबसे बडी दिक्कत यही है कि पैक्स bankrupt हो जाता है जब तक उसका वाइंडिंग-अप का काम समाप्त नहीं होता है। नया पैक्स बन नहीं सकता है इसकी कानूनी व्यवस्था करनी पडेगी तो पैक्स को साइड में रखकर वाइंडिग अप का काम शुरू हो जाए। नए पैक्स की रचना हो और सहकारिता आगे बढ जाए। हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि सभी के सभी पैक्स का कम्प्यूटराइजेशन पूरा हो इसमें भारत सरकार भी अपना बडा योगदान देने वाली है और सारे पैक्स का कम्प्यूटराइजेशन बहुत कम समय में करने के लिए भारत सरकार योजना लेकर आएगी।

मित्रों, कम्प्यूटराइजेशन के साथ-साथ एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने की कवायत चालू की है जो पैक्स, डीसीबी और नाबार्ड तीनों को जोडेगा और एक ही सॉफ्टवेयर से

पैक्स, डिस्ट्रिक कॉपरेटिव बैंक, और नाबार्ड की अकाउन्टिंग सिस्टम एक लय के साथ होगा और सभी भाषाओं में होगा, स्थानीय भाषाओं में भी होगी।

मित्रों, पैक्स को एफपीओ बनाने के लिए भी क्या किया जा सकता है इस पर भी मेरा मंत्रालय काम कर रहा है। मेरा आग्रह है सहकारिता प्रशिक्षण को और पैना करना पडेगा, प्रोफेशनल करना पडेगा। स्किल डेवलपमेंट के सारे एरिया जो सहकारिता को छूते हैं उन सभी एरिया के स्किल डेवलपमेंट की व्यवस्था करनी पडेगी बहुत बडा कॉरपोर्स होता है मगर उसका उचित उपयोग करना है, इसके लिए भी मेरा मंत्रालय एक कार्य योजना बना रहा है। क्रेडिट सोसायटियों की भूमिका और मजबूत करने और नीचे तक ले जाने की जरूरत है जिससे छोटे से छोटे व्यक्ति को क्रेडिट मिल सके। दीपावली का त्यौहार है और हजार रुपये चाहिए किसी को त्यौहार मनाने के लिए, इनकम है मगर आज नहीं है क्योंकि दो महीने पहले घर में बीमारी आ गई थी, तो उसको हजार रुपये मिल जाए उसकी दीपावली अच्छी जाए, इस प्रकार की क्रेडिट सोसायटी नीचे तक बननी चाहिए। ये कोई बैंक नहीं कर सकता बैंक कागज मांगेंगे, अरे भाई इसके पास कागज होते तो हजार रुपये लेने को काहे को आता वो। कागज नहीं है हमारी कॉपरेटिव सोसायटियां जो छोटे-2 लोन देती हैं, आंख की शर्म से देती हैं और मैं मानता हूं इसको हम सभी तक पहुंचाने का काम करेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड में भी पैक्स की भूमिका राज्यों में अभी तक बनी नहीं है। इसको बनाने के लिए हम प्रयास करेंगे। प्रायर्टी सेक्टर लैंडिंग सिर्फ अल्पकालीन रूम नहीं है सभी प्रायर्टी सेक्टर लैंडिंग में कॉपरेटिव की भूमिका बढ़ाने के लिए सभी प्रायर्टी सेक्टर लैंडिंग के भारत के मंत्रालयों के साथ सहकारिता मंत्रालय काम करकर जमीन पर प्रायर्टी लैंडिंग सभी प्रकार के कॉपरेटिव के माध्यम से हो इसके लिए हम काम करेंगे। जैसे स्वसहायता ग्रुप है आज तक देश में स्वसहायता ग्रुपों ने अपनी स्पेशीफाई सोसायटी नहीं बनायी। ये अमूल जो है ना ये स्वसहायता ग्रुपों की स्पेशिफाई सोसायटी है। अमूल की तरह स्वसहायता ग्रुप हर राज्य में अपनी स्पेशिफाई सोसायटी बनाकर छोटी-छोटी स्वसहायता ग्रुपों से बनाई हुई चीजों

के मार्केटिंग की व्यवस्था कर सकता है। इसके लिए भी एक विशेष कानूनी प्रबंध करने की जरूरत है, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं । मत्स्य सहकारिता के लिए भी सबसे बड़ा समुद्र किनारा हमारे पास है इसका दोहन हम प्रर्याप्त मात्रा में नहीं कर सकते। छोटे मछुवारों के पास बड़ी-बड़ी चीजें लेने का पैसा नहीं है, न नेट लेने का पैसा, न यांत्रिक बोट लेने का पैसा है, तो मछुवारा कॉपरेटिव बनाकर उनको एक प्लेटफार्म देंगे जिससे इसका मुनाफा मछुवारों के बैंक अकाउन्ट में पहुंचे इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिए भी हमने काम किया है। इसी प्रकार से ट्राइबल क्षेत्र में जनजातीय सहकारिता लाकर जो वन उत्पाद है उसके लिए भी कॉपरेटिव बनाकर मार्केटिंग की व्यवस्था नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हम करने जा रहे हैं।

मित्रों, सहकारी समितियों का बुनियादी खाका और देश भर के हर राज्य के कानून के अन्दर एक प्रकार की सिनर्जी हो इस प्रकार का प्रयास भी हमने हाथ में लिया है। मुझे मालूम नहीं है कि सफलता कितनी मिलेगी मगर हमारा इरादा नेक है इसलिए विश्वास है कि इसमें सफलता जरूर मिलेगी और हम जरूर सफल होंगे । आज इतने सारे सहकारिता आन्दोलनों के दिग्गज नेता आए हैं, वर्क्स ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, पारदर्शिता भर्ती प्रक्रिया और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया और खुला सदस्य, सभासद बनाने का खुला कार्यक्रम सहकारिता संस्थाओं ने करना पडेगा। ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट पारदर्शिता, भर्ती में पारदर्शिता और चुनाव के अन्दर पारदर्शिता इसको हमें लाना ही होगा तब जाकर हम आगे बढ पाएंगे वरना हम भी कालबहया हो जाएंगे। मोदी जी ने इस आन्दोलन को गति देने के लिए एक बहुत बडा निर्णय किया है और मोदी जी के इस निर्णय को सफल बनाने के लिए और सहकारिता आन्दोलन को एक द्रुत गति के साथ आगे बढाने के लिए हमें सहकारिता क्षेत्र में जो आंतरिक परिर्वतन करने की जरूरत है उस पर भी आत्म निरीक्षण कर बल देना पड़ेगा।

मित्रों, सहकारिता कॉमन सिर्विस सेन्टर की कल्पना भी हमारा मंत्रालय कर रहा है। नेशनल डेटा बेस के लिए भी हमारा मंत्रालय आगे बढ रहा है और नेशनल कॉपरेटिव

इनिशिएटिव बनाने के लिए भी चार जगह से दर्खास्त मिली है। मुझे लगता है कि प्रोफेशनल युनिवर्सिटी की जगह कोई बड़ा कॉपरेटिव संस्थान आगे आए तो अच्छा होगा। कॉपरेटिव युनिवर्सिटी बनाने की जरूरत है। कोई अपनी दर्खास्त लेकर आए तो जरूर अच्छा काम हो सकता है।

मित्रों, Chandrapal जी ने कुछ बातें दबे स्वरों में कही हैं। मैं उनको इतना कहता हूँ कि आप न बोले होते तो भी चलता बोले भी हैं अच्छा होता मुखर होकर बोलते तो भी अच्छा हुआ बोले मगर सारी चीजों की मुझे मालुमात है क्योंकि मैं आप में से ही हूँ अर्बन कॉपरेटिव बैंक के प्रॉब्लम, टैक्सेशन के प्रॉब्लम, भेदभाव पूर्ण रवैया, सरकार का पक्षपात, सरकारी कर्मचारियों का पक्षपातत इन सारी चीजों से मैं अवगत हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ इस क्षेत्र के साथ कोई अन्याय नहीं कर पाएगा इतना भरोसा रखो और इसीलिए मोदी जी ने सहकारिता को प्राथमिकता दी है। आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न में सहकारिता के आन्दोलन को प्रमुख स्थान दिया है और इसीलिए **सहकार से समृद्धि** का मंत्र नरेन्द्र मोदी जी ने दिया है क्योंकि हम चाहते हैं कि सम-विकास होना चाहिए विकास सर्वस्पर्शी होना चाहिए, विकास सर्व समावेशक होना चाहिए, विकास के मॉडल के अन्दर सबको छूने की ताकत होनी चाहिए और विकास का मॉडल सबको समाहित करने के लिए बाहें फैलाकर खडा होने का मॉडल होना चाहिए और वो कॉपरेटिव के अलावा सम्भव नहीं है इसीलिए कॉपरेटिव मंत्रालय की रचना की गई है। चीनी मिलों की भी बहुत सारी समस्याएं हैं, कई जगह हमारे तृस्तरीय एग्रीकल्चरल फाइनेंस के ढांचे को डिस्टर्व करने की भी बात हो रही है मैं इन सब चीजों में अभी कुछ स्पष्टता से नहीं कह रहा हूँ क्योकि विचार चल रहा है सबसे चर्चा भी करनी है परन्तु मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि आपकी समस्या आप जरूर मुझे लिख कर भेजिए छोटी से छोटी चिट्ठी को मैं ध्यान से पढकर इस पर उचित निर्णय करूंगा। अगर लिख कर नहीं भेजेंगे तो भी मैं सामने से सम्पर्क करकर आपकी तकलीफों को समझकर उसके निवारण के लिए प्रोएक्टिव रहूंगा और ये मोदी जी की इच्छा है देश के प्रधानमंत्री

जी की ये मन की इच्छा है कि वो चाहते हैं छोटे से छोटे व्यक्ति को विकास की प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाना, सहकारिता के माध्यम से हर परिवार को समृद्ध बनाना और हर समृद्ध हुए परिवार के सहयोग से देश को समृद्ध बनाना यही सरकार की समृद्धि का मंत्र है और हमें इसके लिए जी जान से लड़ना है। आज मैं यहां आया हूँ, मेरा और मेरे साथी मंत्री जी का आपने स्वागत किया, यहां पर डॉ. साहेब भी अर्जेंटिना से पधारे हैं और मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भारत की सहकारिता क्षेत्र, भारत का सहकारी आन्दोलन, देश भर में गुड प्रेक्टिसेस को साझा करने का, एक्सचेंज करने का एक प्लेटफार्म बन सकता है। आप इनिशिएटिव लेकर ऐसी किसी संस्था का हेडक्काटर भारत में बनाइए जो दुनिया भर की कॉपरेटिव गुड प्रेक्टिसेस का एक्सचेंज माध्यम बने हम आपका स्वागत करने के लिए यहां पर तैयार है और मैं फिर से एक बार कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी की मन की इच्छा है कि सहकारिता के आधार पर भारत की अर्थनीति के विकास का एक नया अध्याय लिखा जाए। मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को चरितार्थ करने के लिए सहकारिता क्षेत्र को प्रमुख भूमिका निभानी होगी और सहकारिता को हमें संस्कार बनाना होगा और महत्वपूर्ण भूमिका जो हम निभाएंगे वो आने वाली पीढियां भी याद रखेंगी इसका मुझे विश्वास है। आज देश भर से ऑनलाइन आंकडा जो मेरे खडा होने से पहले संचालिका महोदया ने कहा 4.25 करोड लोग ऑनलाइन जुडे थे, बहुत सारी समितियां भी जुडी हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक कॉपरेटिव बैंक जुडे हैं। मैं सभी सहकारिता आन्दोलन के आन्दोलनकारियों को बहुत-बहुत मन से धन्यवाद करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि नई ऊर्जा के साथ सहकारिता आन्दोलन को एक नए प्राण भरने की कवायद जो मोदी जी ने की है, हम सब साथ मिलकर इसको सफल बनाएंगे।

*****